



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1942]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2014/आश्विन 1, 1936

No. 1942]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2014/ASHVINA 1, 1936

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2014

**का.आ. 2464(अ).**—केंद्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 30 के उप-नियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति से मिलकर बनने वाले एक अधिकरण अर्थात् श्री जितेश जॉन, निदेशक, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 का गठन करती है और 19,12,499 रुपये (उन्नीस लाख बारह हजार चार सौ उनन्चास रुपये मात्र) की राशि इंदिरा गांधी कारीगर कल्याण संघ सेवालकुलम, संकरणकोइल, टी.के तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु द्वारा खादी और ग्रामोद्योग को संदेय है, का निर्णय करने के लिए विवाद के प्रश्न को निर्दिष्ट करती है और यदि ऐसा नहीं है तो उक्त धारा की उपधारा (1) के अर्थात्गत कितनी राशि संदेय है।

2. उक्त अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा. सं. सी-18019/14/2014/केवीआई-पी]

बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2014

**S.O. 2464(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of one person, namely, Shri Jithesh John, Director, Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 and refers the question of dispute to decide whether a sum of Rs. 19,12,449/- (Rupees nineteen lakh twelve thousand four hundred and forty nine only) is payable by Indira Gandhi Artisan's Welfare Association Sevalkulam, Sankarankoil, T.K. Tirunelveli Dist., Tamilnadu to the Khadi and Village Industries Commission, and if not so, what amount is payable, within the meaning of sub-section (1) of said section.

2. The headquarter of the said Tribunal shall be at New Delhi.

[F. No. C-18019/14/2014-KVI-P]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

3814 GI/2014